

Court No. - 12

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 9757 of 2024

Petitioner :- Aslam

Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Home Lko.

Counsel for Petitioner :- Smt. Nalini Prakash Jain

Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Saurabh Lavania, J.

Heard Smt. Nalini Prakash Jain, learned counsel for the petitioner, Sri Ajay Kumar Srivastava, learned AGA for the State of U.P. and perused the record.

By means of this petition, the petitioner has sought the following main relief:-

"Issue a writ, order or direction of nature of CERTIORARI thereby quashing the notice issued against the petitioner under Section-3 of Uttar Pradesh Goonda Control Act 1970 dated 03 May 2024, in which case Crime No. 212/2015, under Section-147, 148, 149, 323, 504, 506 Indian Penal Code and 3 (1) (10) SC/ST Act Police Station- Gudamba, Lucknow, Case Crime No- 217/2020 Under Section-323, 504, 506, Indian Penal Code Police Station Gudamba, Lucknow, Case Crime No- 307/2022, Under Section 147, 148, 149, 323, 325, 506, 427, Indian Penal Code, Police Station- Gudamba, Lucknow, Case Crime No-383/2023 310 Section-147, 148, 149, 323, 504, 506 Indian Penal Code, Police Station- Gudamba, Lucknow and Case Crime No-19/2024 Under Section 506, 307, 504, 34 Indian Penal Code, Police Station- Gudamba, Lucknow and beat information Ro. Amar Report: No.- 40 time 14:22 dated 28-02-2024 against the petitioner contained as Annexure No. 1 to this writ petition, in the interest of justice."

Vide order dated 02.12.2024, the Commissioner, Lucknow Division, Lucknow (in short "appellate authority") rejected the Appeal No. 4427/2024 (Aslam vs. State of U.P.) filed under Section 6 of U.P. Control of Goondas Act, 1970 (in short "Act of 1970"). The relevant portion of the order dated 02.12.2024 is extracted hereunder:-

"5- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अपील में, अपील में के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य संलग्नकों तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रश्नगत अपील वाद संख्या-155(111)/2024 धारा-3 उ 0 प्र 0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना गुडम्बा सरकार बनाम असलम में पारित संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ के आदेश दिनांक 25-10-2024 के विरुद्ध दाखिल की गई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या-212/2015 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भा 0 द 0 वि 0 व 3(1)(10) एस 0 सी 0/एस 0 टी 0 एक्ट थाना गुडम्बा, मुकदमा अपराध संख्या 217/2020 धारा 323, 504, 506 भा 0 द 0 वि 0 थाना गुडम्बा लखनऊ, मुकदमा अपराध संख्या 307/2022 धारा 147, 148, 149, 323, 325, 506, 427 भा 0 द 0 वि 0, मुकदमा अपराध संख्या 383/2023 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506 भा 0 द 0 वि 0, मुकदमा अपराध संख्या 19/2024 धारा 506, 307, 504, 34 भा 0 द 0 वि 0 थाना गुडम्बा एवं बीट सूचना रपट दिनांक 28-02-2024 पंजीकृत होने के आधार पर गुण्डा घोषित करते हुये जनपद लखनऊ की सीमा से 04 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ

द्वारा नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी कर अपीलकर्ता को बचाव का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अपीलकर्ता को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया किन्तु अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया जा सका जिससे संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

अवर न्यायालय के आदेश में वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता भा0 द 0 वि0 के अध्याय 16, 17 एवं 22 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करने का अभ्यस्त है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) लखनऊ ने अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देकर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना करते हुये गुणदोष पर मुखर आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

6- उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अपील आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। आदेश की एक प्रति अवर न्यायालय को भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।"

Upon due consideration of the aforesaid and also the grounds taken in the memo of appeal, copy of which placed before this Court is taken on record, this Court is of the view that the order dated 02.12.2024 is liable to be interfered with, as the same has not been passed after considering the grounds taken in the appeal and being so, the impugned order is not a reasoned and speaking order. It is accordingly **set-aside**. The matter is remanded back to the authority concerned for decision afresh as per law including the law settled in the judgment(s) passed by this Court in the case of **Imran Alias Abdul Quddus Khan vs. State of U.P. and others; 2000 Cri. L.J. 1328, Lalani Pandey @ Vijay Shaker Pandey vs. State of U.P. and others; [2011(1) JIC 503 (All)(LB)]** and **Umar @ Mohd Umair vs. State of U.P. and another; [2024(3) JIC 316 (All)]**, expeditiously.

The instant petition is **allowed** in above terms.

Order Date :- 20.12.2024

Arun/-